एम**०एच० खान,** सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, देहरादून

समाज कल्याण अनुभाग-3

देहरादून दिनांक 20 जुलाई, 2012

विषय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु दशमीतार छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) की मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या—16/6/2012—पी०पी०(पी०पी०आर०) दिनांक 29 जून, 2012 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 में उक्त योजनान्तर्गत धनराशि रू० 1,64,00,000/— (रू० एक करोड़ चौंसठ लाख मात्र) की वित्त विभाग के शासनादेश संख्या संख्या—321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 के कम में बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू० 79.00 लाख (रू० उन्नासी लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्याः 321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 वि उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। भारता सरकार द्वारा दी गयी उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव पुनर्विनियोग के माध्यम से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रस्ताव पुनविनियोग के माध्यम से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। 2 आय—व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही

व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अवचनद्व मदों में से व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय। योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

 उक्त आवंटित धनराशि किसी मद पर व्यय करने से पूर्व जिसमें वित्तीय इस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय

अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंदित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकरिनक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल शे दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या—15 "आयोजनागत्" शब्द स्पष्ट किया जाए अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

5. वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धन्याशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यथ की स्थिति से

यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

भितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। गित्रव्ययिता/अबचनवद्व की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहगति कराना सनिश्चित करें।

यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनसंशि की आवश्यकता हो हो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित

अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

बीठएम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सानिश्चित करें।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुवान संख्या—15 के आयोजनागत एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं—0102—अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृदित (१०० प्रतिशत केंंंग्ला के मानक मद 21-छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन के नामे डाला जाएगा।

यह आवंटन अनुदान संख्या—15 के अलोटमैंट आई डी संख्या \$1207150816 दिनांक 19 जुलाई, 2012 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

सलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(एम०एच० खान) सचिव।

पृष्ठांकन संस्थाः <u>१ २</u> (1) / XVII-3/12-07(65)/2007 तद्दिनांकित। प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुंमाऊँ उत्तराखण्ड।

निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।

जिलाधिकारी, देहराद्न।

वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारो, देहरादून, उत्तराखण्ड ।

वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।

अवर सचिव, अल्पंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्याः 16/06/2012-पी0पी0 (पी0पी03गर0) दिनांक 19 जून, 2012 के क्रम में सूचनार्थ प्रेनित।

बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिवार देहरादन।

समाज कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सिववालय परिसर,

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

आदेश पंजिका।

आज्ञा से (answar) (एम०एव० खान) सचिव।